Madhya Pradesh Journal of Social Sciences
A biannually Journal of M. P. Institute of Social Science Research, Ujjain
ISSN: 0973-855X (Vol 29 No 4, April 2024)

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा जाति प्रथा

डॉ. बलबीर सिंह
सहायक आचार्य, अहिंसा एवं शांति विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं–341306 (राजस्थान)
Mail ID-balbeerscharan29@gmail.com

डॉ. लिपि जैन
सहायक आचार्य, अहिंसा एवं शांति विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं–341306 (राजस्थान)
Mail ID-lipijainjvbi@gmail.com

शोध–सारांश

भारत में विविधता में एकता हमारी संस्कृतिक पहचान रही है। भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत विविधताएं भारत में पाई जाती है, इन विविधताओं के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता का भाव भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान रही है। प्राचीन काल से भारत में जाति प्रथा प्रचलित रही है, जाति व्यवस्था का प्रारंभ वैदिक काल से ही माना जाता है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीन जातियों को मान्यता प्राप्त थी।उत्तर वैदिक काल में शूद्र वर्ण का भी उद्भव हुआ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्ध चार वर्ण भारतीय समाज में विद्यमान थे। कभी इनका आधार वर्ण व्यवस्था रही है। वर्तमान स्वरूप में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव कम नजर आता है और विभिन्न जातियां भारत में पाई जाती है। राजतंत्र में वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था। वर्तमान लोकतांत्रिक परिदृश्य में वर्ण व्यवस्था के स्थान पर समानता एवं सभी को अवसर की समता मिली हुई है और कोई भी व्यक्ति जातिगत आधार पर नहीं बल्कि अपनी योग्यता एवं नेतृत्वशीलता के आधार पर राजनीति में सहभागिता कर सकता है, लेकिन फिर भी जाति प्रथा ने भारत की राजनीति को काफी प्रभावित किया है। अतः भारत में जाति व्यवस्था एवं उसके राजनीति पर पड़े प्रभावों का विवेचन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता के लिए सभी को समान अधिकार, अवसरों की समानता, न्याय, सह–अस्तित्व एवं समतामूलक समाज अति आवश्यक है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जातिवाद की भावना राष्ट्रीय विकास तथा लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति में अवरुद्ध बनती है। इसके साथ–साथ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि, जातिवाद के कारण व्यक्तियों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र–प्रेम तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना में कमी आती है। कुछ समाजशास्त्री यह भी मानते हैं कि जाति व्यवस्था ने प्रगति एवं राजनीति को काफी प्रभावित किया है और इससे राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियां उभर कर आई है। राजनीति में जातिवाद के हस्तक्षेप से लोकतंत्र के मौलिक आयाम प्रभावित होते है। जातिवाद व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। जातिवाद की प्रवृत्तियों को रोकना और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्था में इसके प्रभाव को कम करना राष्ट्र विकास एवं राष्ट्र प्रगति के लिए अपरिहार्य है।

मुख्य शब्द : वर्णव्यवस्था, समतामूलक समाज, राष्ट्रीय नेतृत्व, विविधता में एकता, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय विषमताएं, सामाजिक एकरूपता, लोकतांत्रिक समाज।

प्रस्तावना :

भारत में विविधता में एकता हमारी संस्कृतिक पहचान रही है। भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत विविधताएं भारत में पाई जाती है, इन विविधताओं के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता का भाव भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान रही है। प्राचीन काल से भारत में जाति प्रथा प्रचलित रही है, जाति व्यवस्था का प्रारंभ वैदिक काल से ही माना जाता है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीन जातियों को मान्यता प्राप्त थी।उत्तर वैदिक काल में शूद्र वर्ण का भी उद्भव हुआ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्ध चार वर्ण भारतीय समाज में विद्यमान थे। कभी इनका आधार वर्ण व्यवस्था रही है। वर्तमान स्वरूप में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव कम नजर आता है और विभिन्न जातियां भारत में पाई जाती है। राजतंत्र में वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था। वर्तमान लोकतांत्रिक परिदृश्य में वर्ण व्यवस्था के स्थान पर समानता एवं सभी को अवसर की समता मिली हुई है और कोई भी व्यक्ति जातिगत आधार पर नहीं बल्कि अपनी योग्यता एवं नेतृत्वशीलता के आधार पर राजनीति में सहभागिता कर सकता है, लेकिन फिर भी जाति प्रथा ने भारत की राजनीति को काफी प्रभावित किया है। अतः भारत में जाति व्यवस्था एवं उसके राजनीति पर पड़े प्रभावों का विवेचन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता के लिए सभी को समान अधिकार, अवसरों की समानता, न्याय, सह–अस्तित्व एवं समतामूलक समाज अति आवश्यक है। इन व्यवस्थाओं में जाति व्यवस्था द्वारा काफी बाधा उत्पन्न होती है और जाति प्रथा के कारण समाज में भेदभाव, अन्याय एवं अवसरवादीता की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। जाति व्यवस्था ने रंग, लिंग, जन्म व्यवस्था, धर्म, विवाह आदि प्रथाओं विविधताओं उत्पन्न किया है तथा राष्ट्रीयता की भावनाएं विकसित करने में बढ़ाएं उत्पन्न की है। राष्ट्रीय तथा प्रजातांत्रिक आदर्श की स्थापना के लिए आवश्यक है कि, समाज में समानता हो।

अध्ययन के उद्देश्य :

- भारतीय राजनीति के स्वरूप को स्पष्ट करना।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था में जातिगत प्रथाओं का प्रभाव परिलक्षित करना।
- भारतीय राजनीति में जातिवाद की भूमिका का अवलोकन करना।
- सत्ता निर्माण की प्रक्रिया में जातिवाद के प्रभाव को स्पष्ट करना।
- शासन संचालन की प्रक्रिया में जातिवाद के प्रभाव को उजागर करना।
- भारतीय राजनीति एवं जातिवाद के स्वरूप को स्पष्ट करना।
- भारतीय लोकतंत्र में जातिवाद के विविध पक्षों का अवलोकन करना।

अध्ययन पद्धति :

उपरोक्त शोध पत्र तैयार करने के लिए तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। भारत में अलग–अलग क्षेत्रों में विविधताएं पाई जाती है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। भारतीय राजनीति एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, इस बिंदु का तलरूस्पर्शी एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन कर शोध पत्र तैयार किया गया है।

जातिवाद का अर्थ एवं परिभाषा :

जातिवाद एक जाति विशेष के सदस्यों के मन में यह भावना कि वे अपने जाति के लोगों के साथ जुड़ें और अपनी जाति के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, चाहे शासन सत्ता द्वारा संसाधनों का वितरण हो या फिर राजनीतिक सहभागिता की बात हो अपनी जाति का ही अधिक वर्चस्व एवं प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। नागरिकों में इस प्रकार की भावना बलवती होती है, तो वहां जातिवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है।मानव भावनाओं का संकुचित होना एवं अपनी जाति को ही सर्वश्रेष्ठ मानना ही जातिवाद है।डॉ. कैलाशनाथ शर्मा के अनुसार जातिवाद या जाति भक्ति एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है, जो देश या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान जाति गत एकता और जाति की सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हो।

लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं जातिवाद के प्रमुख आयाम :

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन प्रणाली का आधार बनी हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शासन में जन सहभागिता, शासन सत्ता के गठन हेतु चुनावी प्रक्रिया, सत्ता में विभागों एवं संसाधनों का वितरण तथा अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को जाति व्यवस्था ने काफी प्रभावित किया है।जाति प्रथा से लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार प्रभावित होती है और शासन सत्ता के अंतर्गत कैसे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। इस बात का अवलोकन करना आवश्यक है। प्रो. रजनी कोठारी ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका विषय पर अनुसंधान किया है। उन्होंने यह माना कि भारत में अनेक जातियां पाई जाती है और संपूर्ण राष्ट्र में जाति विशेष का प्रभाव नहीं पाया जाता का प्रभाव नहीं दिखता लेकिन अलग–अलग क्षेत्र में जिन जातियों का बाहुल्य एवं वर्चस्व है वहां उनका प्रभाव नजर आता है। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण रचना भारतीय राजनीति में जाति(ब्ंज पद प्दकपंद च्वसपजपबे) में भारतीय राजनीति में जातिवाद की प्रवृत्ति को विस्तृत रूप में उल्लेखित किया है।प्रो. कोठारी ने जाति प्रथा के तीन स्वरूप प्रस्तुत किए हैं –

- लौकिक स्वरूप
- एकीकरण का स्वरूप
- चैतन्य स्वरूप

जयप्रकाश नारायण ने तो यहां तक भी कहा है कि भारत में जाति एक अत्यधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। हेरल्ड गोल्ड ने स्पष्ट करते हुए बताया कि राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय समाज में जाति एक पारंपरिक पहलू है।स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माण तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में जातिवाद का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था लेकिन वर्तमान समय में चुनावी प्रक्रिया में सत्तानिर्माण, निर्णय निर्माण, प्रशासन में, मंत्रिमंडल के निर्माण में, दबाव समूह, मतदान की प्रवृत्ति के अंतर्गत और राज्य राजनीति में भी जातिवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है।

भारत में जातियां एकजुट होकर राजनीति तथा प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करती है। चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे कोई नए कानून के निर्माण की बात हो अथवा किसी कानून में संशोधन की चर्चा हो, हर जगह है जातियों का प्रभाव नजर आता है। प्रत्येक जाति का यह लक्ष्य होता है कि सरकार द्वारा जो भी निर्णय किया जाए उसमें उनकी जाति को अधिक तवज्जो दिया जाए या फिर उनकी जाति के लोगों के हितों के अनुरूप सरकार निर्णय करें।

भारत की राजनीति में जितने भी दल सक्रिय हैं और जो भी दल अपना प्रभावशाली स्थान रखते हैं, उन सभी में चाहे टिकट का वितरण हो चाहे दल की सदस्यता हो हर जगह व्यवहार में जातिवाद का प्रभाव ही परिलक्षित होता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य है उस जाति के उम्मीदवार को ही प्राय राजनीतिक दलों द्वारा अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया जाता है।राजस्थान की राजनीति की बात करें तो जाट बाहुल्य क्षेत्र में प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दल जाट समुदाय के उम्मीदवार को अपना टिकट देना प्राथमिकता समझता है और जिस क्षेत्र में राजपूत समुदाय की बाहुल्यता है उसे क्षेत्र में भी राजपूत समुदाय की उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं। अलग–अलग राज्यों में और क्षेत्रों में जिन जातियों का बाहुल्य है उनके समुदाय में से किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना प्राय हर राजनीतिक दल की प्राथमिकता रहती है।

मतदान व्यवहार की प्रवृत्ति भी एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कि चुनाव में मतदाता के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। प्रायः देखा जाता है कि जहां जिस जाति का उम्मीदवार चुनाव में प्रत्याशी बनता है, उसे उसकी जाति के वोट बैंक से ही ज्यादा अपेक्षा रहती है। इस दिशा में हम यह देख भी सकते हैं कि मतदाता भी अपने जाति के उम्मीदवार के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं और वह उम्मीदवार की योग्यता निष्पक्षता एवं कर्माता को ध्यान में रखने के साथ–साथ जाति के महत्वपूर्ण तत्वों को भी मतदान करते समय ध्यान में रखते हैं। मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करने में भी भारत की राजनीति में जातिवाद की भावना महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन चुकी है।

राजनीतिक दलों के साथ–साथ चुनावी प्रक्रियाओं में जातिवाद का प्रभाव अनवरत दिखलाई पड़ता है लेकिन मंत्रिमंडल के निर्माण की प्रक्रिया में भी जातिवाद का प्रभाव बना रहता है। जिस दल को सत्ता प्राप्त होती है उस दल के मुखिया द्वारा जब केंद्र की राजनीति में राष्ट्रपति को तथा राज्यों की राजनीति में राज्यपाल को मंत्रिमंडल निर्माण करने का परामर्श दिया जाता है। इस दिशा में क्षेत्रीयता के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन हो इस बात का तो ध्यान रखा ही जाता है इसके साथ–साथ अलग–अलग जातियों का मंत्रिमंडल में कितना प्रतिनिधित्व है इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि कोई सत्ता प्राप्त राजनीतिक दल इस प्रक्रिया को नहीं अपनाता है तो उसे जातिगत समुदायों के विरोध का सामना करना पड़ता है है।

भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के साथ–साथ दबाव समूहों का भी काफी प्रभाव रहता है और अलग–अलग आधार पर गठित दबाव समूहों के गठन में जातिवाद की प्रवृत्ति भी एक महत्वपूर्ण आधार रही है। भारत में जातिगत आधार पर अनेक दबाव समूह गठित हुए हैं और वह वर्तमान समय में सरकार के निर्णय को सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मण, जाट, राजपूत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गुर्जर, माली और अन्य जातियों के भी अपने–अपने दबाव समूह बने हुए हैं। हर दबाव समूह अपनी–अपनी जातियों के हितों के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद भी जातिवाद पर संगठित दबाव समूह सरकार के निर्णय एवं योजनाओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

आरक्षण की व्यवस्था का भी मूलभूत आधार जाति व्यवस्था ही है।अलग–अलग जातियों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्हें आरक्षण मिला हुआ है। हालांकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की आरक्षण की व्यवस्था जातिगत आधार पर नए होकर आर्थिक स्थिति पर आधारित है। यह व्यवस्था जातिवाद के स्थान पर लोगों की आर्थिक स्थिति को आधार मानती है, जो कि जातिवाद के प्रभाव को कम करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा सकता है।

राज्य राजनीति में भी जातिवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है, जिन राज्यों में जो जातियां बाहुल्यता की स्थिति में हैं, सत्ता पर प्राय उनका ही कब्जा बना रहता है। राजस्थान की राजनीति में जाट, ब्राह्मण तथा राजपूत, गुजरात की राजनीति में पाटीदार तथा क्षत्रिय, केरल की राजनीति में हिंदू, क्रिश्चियन तथा मुसलमान, आंध्रप्रदेश की राजनीति में कम्मा तथा रेड्डी आदि जातियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है।

निष्कर्ष :

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जातिवाद की भूमिका एवं इसके प्रभाव एक नकारात्मक पक्ष माना जा सकता है। जातिवाद की भावना राष्ट्रीय एकता के मार्ग में महत्वपूर्ण बाधा बनती है और इससे राष्ट्रीय एकीकरण के स्थान पर व्यक्तियों में अपनी जाति के प्रति ज्यादा समर्पण की भावना का उद्भव होता है। राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होती है और जातिगत हितों को अधिक महत्व मिलने लगता है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जातिवाद की भावना राष्ट्रीय विकास तथा लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति में अवरुद्ध बनती है। इसके साथ–साथ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि, जातिवाद के कारण व्यक्तियों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र–प्रेम तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण

की भावना में कमी आती है। कुछ समाजशास्त्री यह भी मानते हैं कि जाति व्यवस्था ने प्रगति एवं राजनीति को काफी प्रभावित किया है और इससे राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियां उभर कर आई है। राजनीति में जातिवाद के हस्तक्षेप से लोकतंत्र के मौलिक आयाम प्रभावित होते है। जातिवाद व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। जातिवाद की प्रवृत्तियों को रोकना और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्था में इसके प्रभाव को कम करना राष्ट्र विकास एवं राष्ट्र प्रगति के लिए अपरिहार्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. कुमार, पवन, भारतीय राजनीति की दशा एवं दिशा, वंदना पब्लिकेशंस, नई दिल्ली(2011)।
2. शर्मा, रिचा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राखी पब्लिकेशंस शाहदरा, दिल्ली(2011)।
3. खंडेला, मानचंद, भारतीय राजनीति का बदलता परिदृश्य, अरिहंत पब्लिशिंग हाउस, जयपुर (2008)।
4. कश्यप, सुभाष, भारतीय राजनीति और संविधान, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली(1999)।
5. मल्होत्रा ए.पी., भारतीय शासन और राजनीति, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली (2013)।
6. भाकरे, आर.पी., भारतीय राजव्यवस्था इशीका पब्लिशिंग हाउस दिल्ली (2015)।
7. राजकुमार, भारतीय शासन और राजनीति, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली (2009)।
8. सुधीर वेददान, भार्गव नरेश, चतुर्वेदी अरूण, संजय लोढ़ा, भारतीय शासन के संरचनात्मक आधार, वाणी प्रकाशन(2023)।

9- Sharma] Sanjeev Kumar] Nain] A nusuiya, State Politics in Contemporary India] Sanidhya Books] Delhi(2022).